THE HOMEBASED WORKERS (PROTECTION) BILL,- 1994

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to provide for the protection of the homebased workers in the country and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Madam, I introduce the Bill.

THE MARRIED WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS) BILL, 1994

SHRIMATI VEENA VERMA (Madhya Pradesh): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to protect the rights of a married women and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI VEENA VERMA: Madam, I introduce the Bill.

THE NATIONAL COMMISSION FOR CHILDREN BILL, 1994

SHRIMATI VEENA VERMA (Madhya Pradesh): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to constitute a National Commission for protecting rights and interests of children and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI VEENA VERMA: Madam, I introduce the Bill.

The reservation of posts for women in Government services 1994

SHRIMATI VEENA VERMA (Madhya Pradesh): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the reservation of posts for women in Government services for improving their lot in the society by making them financially independent and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI VEENA VERMA: Madam, I introduce the Bill.

THE PREVENTION OF INFLUX OF FOREIGN NATIONALS IN THE COUNTRY BILL, 1991—Contd.

श्री संघ प्रिय गौतम : (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, चर्चा प्रारम्भ करते समय मैं कह रहा था कि विदेशी से वहां के राष्ट्रिक भ्रमण के लिए नहीं आते, पर्यटन के लिए नहीं आते, नौकरी के लिए नहीं आते, व्यवसाय के लिए नहीं आते, अधिकृत रूप से निश्चित समय के लिए नहीं आते या एक ही देश में जो दो विभिन्न धर्मों और वर्गों के लोग हैं वहां पर प्रताड़ित बहुसंख्यक वर्ग है उनके द्वारा प्रताड़ित होने पर नहीं आते या दो देशों के बीच में संघर्ष छिड़ जाने और लड़ाई छिड़ जाने के कारण नहीं आते, वे निःसंदेह ऐसे राष्ट्रिक होते हैं कि अनधिकृत रूप से हमारे राष्ट्र में आते हैं । पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या हमारे देश में ज्यादा हो गई है । इससे हमारे देश में जनसंख्या का भारी बोझ लाद दिया गया है और हमारे इस देश की सरकार हमारे देश के नागरिकों को जो आवश्यक दैनिक सुविधाएं हैं वे भी देने में समर्थ नहीं हो पा रही है । बार-बार इस सदन में चर्चा करते समय कहा गया है आज भी हमारे देश में लगभग आधी जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे रह रही है । करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, करोड़ों लोग बिना दवा के

मर जाते हैं, करोड़ों लोगों को दो टाइम खाना तो दरकिनार एक टाइम खाना भी भरपेट नहीं मिलता, करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता । ऐसी स्थिति में जब विदेशी राष्ट्रिक गैरकानूनी तरीके से हमारे देश में आकर जमा हो जायेंगे तो हमारे देश की परिस्थिति क्या होगी यह एक बहुत ही गम्भीर चिंता और विचारणीय विषय है । रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, दवा और सुरक्षा आदि जो आवश्यक चीजें हैं क्या हम अपने देश के नागरिकों को दे पायेंगे ? यदि नहीं दे पायेंगे तो समाज में तनाव पैदा होगा, नौजवानों में असंतोष व्याप्त होगा और उस असंतोष के कारण क्या परिस्थितियां पैदा होंगी ? वही परिस्थितियां पैदा होंगी जो मणिपुर में हो रही हैं, नागालैंड में हो रही हैं या अन्य प्रदेशों में हो रही हैं जिनसे उग्रवाद और आंतकाद पैदा होता है और देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा होता है जिसको हम और आप देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं । क्या हम लोग फिर से उन परिस्थितियों को पैदा करना चाहते हैं ? मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग बहुत समय से रह रहे है। हिन्दू, बौध, जेन, पारसी रह रहे है। मैं क्षमा चाहूंगा, सच है लेकिन कड़ुवा है, पर मैं भाषा कड़ुवी नहीं कहूंगा, सिख भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं। सभी लोग एक राष्ट्र के सिद्धांत में विलीन हो गये हैं। लेकिन एक विशेष धर्म या मजहब के अनुयायियों ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को अपनाया, वे एक राष्ट्र के सिद्धांत में विलीन नहीं हो सके और यही कारण है कि हमारे देश को विभाजन देखना पड़ा। हमारे देश के टुकड़े हुए। क्या ईमानदारी से आज हम देखते हैं कि पूरी तरह से एक राष्ट्र के सिद्धांत का विचार नष्ट हो गया है? क्या वह विचार पूरी तरह से मर गया है? क्या आज भी उस विचार की जड़ें इस देश में हरी नहीं हैं? अगर ईमानदारी से हम देखें तो उस विचार की जड़ें आज भी इस देश में हरी हैं और फिर हम आज आग में घी डालने का काम करने जा रहे हैं जब कि उस वर्ग के लोग बड़ी संख्या में हमारी पड़ोसी राष्ट्रों से जिनका कोई अधिकार इस देश में रहने का नहीं है, उन विदेशी राष्ट्रिकों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, उनको अपने देश में रहते देखकर भी इसको हम नजरदांज कर रहे हैं। महोदया, पिछले दिनों मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जितना दोष उन राष्ट्रिकों का है, इसमें हमारे देश के लोगों का भी दोष कम नहीं हैं। हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने, राजनैतिक दलों ने थोड़े समय की सत्ता हासिल करने के लिये और देश में सस्ती राजनीति करने के लिये, अपने मत बढ़ाने के लिए ऐसे विदेशी नागरिको का अपने देश में बसने में सहयोग किया। उनके राशन कार्ड बनवाये गये मतदाता सूचियों में उनके नाम दर्ज करवाये और उनको अनधिकृत तरीके से बहुत ही ऐसी सुविधायें पहुंचायी हैं, जिससे उनका मनोबल और भी बढ़ा है। महोदया, अगर कहीं फिर वह दो राष्ट्रों का सिद्धांत पनप गया तो इस देश के सामने क्या परिस्थिति आयेगी? जैसा मैंने पहले कहा, 1947 में हम यह देख चुके हैं।

महोदया, हमारे बहुत से विद्वान साथी इस विषय पर बोलने वाले हैं, इसलिये मैं ज्यादा समय न लेकर केवल एक उदाहरण देकर कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा खतरा इससे जो पैदा हुआ वह यह है कि हमारी जनसंख्या में असंतुलन पैदा हो रहा है । विदेशियों की बात आप छोड़िये, हमारे देश के ही अंदर आबादी उधर से इधर होने से कितना असंतुलन बढ़ा है, इसका एक उदाहरण लद्दाख में हमें देखने को मिला है, कश्मीर में देखने को मिला है। आज कश्मीर में हिन्दू नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। वे लोग अपने घर से बेघर हो गये हैं। लद्दाख जो पूर्णतया बौद्ध क्षेत्र था आज वहां बहुत संख्या में गैर-बौद्ध आवास हो गये हैं। इस आबादी के असंतुलन का वहां की संस्कृति पर, वहां की भाषा पर, वहां की लेशभूषा पर और व्यक्तियों के रहन-सहन पर, उनके खान-पान पर कुप्रभाव पड़ रहा है। यह आबादी का असंतुलन जब

[श्री संघ प्रिय गौतम]

हमारे देश के अन्तर्गत स्थित एक सूबे से दूसरे सूबे में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब लोग चले जाते हैं, उससे बिगड़ रहा है तो ये विदेशी राष्ट्रिक हमारे देश में आकर जब बस जायेंगे तो वह असंतुलन बिगड़ने से क्या क्या परिस्थतियां उपन्न होंगी, इसका उदाहरण बिहार राज्य का किशन गंज क्षेत्र है, जिसका जिक्र मैंने उस दिन किया था। आज मैं फिर उसको दोहराना चाहता हूं। आज वहां पर आबादी का असंतुलन इतना बिगड़ गया है कि बंगला देश से आये हुए लोग जो अनधिकृत रूप से वहां घुसपैठ करके आ गये हैं उन्होंने वहां पर लोगों को एक विशेष वेशभूषा पहनने पर मजबूर कर दिवा है। एक विशेष टोपी लगाकर वे स्कूल में जाते हैं, सड़कों या बाजारों में घूमेंगे या एक लंगी पहनकर जायेंगे। यह एक आम लिबास वहां का बन गया है। जो उस लिबास को नहीं पहनता है उसकी पहचान अलग होती है और वह हीन भावना के कारण, भय के कारण उस वेशभूषा को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया हैं। तो यह आबादी का असंतुलन इस देश में बहुत बड़ी संख्या में होने वाला है। महोदया, प्रश्न मानसिकता का है। मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर इस देश के लोगों की मानसिकता एक राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार करने की बन जाये। लेकिन आज हमारे राजनैतिज्ञ देख रहे हैं, इस सदन के सदस्य भी देख रहे हैं कि जब रोजी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक कुरीतियों के मसले आते हैं तो यहां पर चर्चा ना के बराबर होती है लेकिन जब धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद, माइनारिटी और मेजोरिटी का सवाल आता है तो यहा महीनों महीने इस सदन में उस पर कहा जाता है। तो यह कितना संवेदनशील विषय है। यह विषय जो उत्पन्न होते हैं, यह विशेष धर्मो के मानने वाले लोगों के आने से पैदा होते हैं। क्या फिर हम इस देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा करने जा रहे हैं? इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर के बारे में अनेको बातें कही जाती हैं अभी कुछ लोग उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं। गांधी जी पर भी टिप्पणियां की गई। जब बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेदकर दलितों की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनसे यह पूछा गया कि आप देश और दलितों में यदि एक को चुनना हो तो किसे पसंद करोगे। बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेदकर जी ने कहा कि मैं देश को पसंद करूंगा। एक फिर उनसे पूछा गया कि डा. अम्बेदकर और देश के हित में से किसे पसंद करोगे तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि मैं अपने देश के हित को पसंद करूंगा। आज यह भावना लो ों के अन्दर पैदा हो जाए और वह दिखाई देने लगे कि व्यक्ति अपने त कि त धर्म, सम्प्रदाय, जाति वर्ग, पं को पहले पसंद करेगा या देश को पहले पसंद करेगा, अगर देश को पहले पसंद करेगा तो फिर किसी हद तक लोगों को किसी परिस्ि ति में बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन हम देख रहे हैं कि यह लोग इस देश की बात नहीं करते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं। कल ही यहां पर भाषा के ऊपर राष्ट्रीय भाषा के ऊार एक संदर्भ आया था। हमारे कुछ मित्रों ने, किसी ने यह कहा कि अंग्रेजी को हटाया गया तो देश की एकता को खतरा पैदा होगा। यहां भाषा के नाम पर देश टूट सकता है या धर्म के नाम पर देश टूट सकता है या जाति के नाम पर देश टूट सकता है, पंथ के नाम पर देश टूट सकता है या तोड़ने की धमकी दी जा सकती है तो फिर इस प्लाया से हम क्या सबक लेते जा रहे हैं? यह जो विदेशी नागरिक आ रहे हैं, बंगलादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं। कौन पाकिस्तान? वही पाकिस्तान जो आतंकवादियों को प्रशिक्षित कर के हमारे देश में भेजता है। हमारे देश को तोड़ रहा है। वह बंगलादेश जो नागाओं को प्रशिक्षित कर के हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में भेज रहा है, जिसने वहां के अल्पसंख्यक बौद्ध जो थे उनको चकमा बौद्ध को निकाल दिया और वहां से यहां आ गये, आज उन्हें वह वापिस लेने को तैयार नहीं है। उनके घरों, पर कब्जा कर लिया,

जमीनों पर कब्जा कर लिया, उनके काम पर कब्जा कर लिया। उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। आज वह निस्सहाय हमारे देश में पड़े हुए हैं। असहाय सरकार उनको वापिस भेजने में नाकामयाब हो रही है। बंगलादेश और पाकिस्तान से इतनी बड़ी संख्या में अनधिकृत रूप से नागरिकों का आना निस्सन्देह हमारे देश में सामाजिक संतुलन बिगाड़ेगा, हमारी जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ेगा, हमारे देश की आबादी के ऊपर बोझ बन कर हमारे देश की व्यवस्था को खराब करेगा। हमारे देश में दो राष्ट्र के सिद्धांत को बढ़ावा देगा और हमारे देश को विभाजन का खतरा पैदा होगा। इसलिए मैं माननीय कृष्णलाल शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करते हुए निवेदन करूंगा कि यह जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनकी सीमाओं पर कांटों के तार लगाए जाएं और सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई जाए, सुरक्षा पट्टियां बनाई जाएं और सन् 1971 से पहले या जो भी समय उपयुक्त समझा जाए गांवों में जो लोग रहते हैं उनके कुटुम्ब रजिस्टरों का परीक्षण और निरीक्षण कर के उसके पहले जो लोग आए थे उनके बाद में जो लोग आए हैं, पिछले सालों में जो मत पड़े हैं उनका निरीक्षण कर के कितने भी विदेशी नागरिक यहां पर आए हैं उनकी अलग से पहचान की जाए। उनकी एक अलग सूची बनाई जाए। उसके बाद यह सरकार उनके देशों को उनको भेजने की व्यवस्था करे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय श्री शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI HIPHEI (Mizoram): Thank you very much, Madam Vice-Chairman. Madam, I am very happy to be one of the participants on this very important Bill moved by my colleague Mr. Krishan Lal Sharma. The Bill is titled: "The Prevention influx of Foreign Nationals in the Country Bill, 1991'. This means, it should have been introduced way back in 1991.

When I saw this Bill, the question came to my mind as to why we had this influx of foreign nationals from across the border. The answer is obvious, Madam. The answer is that India is a better country to live in than the neighbouring countries. This shows how lucky we are; how lucky we, Indians, are. I am proud of my country.

Madam, in 1989, when the question of apartheid in South Africa was discussed at Barbados, I said very proudly that India was full of differences, that India was full of diversities, but that we maintained unity in diversity. Today, the foreign nationals are coming to our country only because they think that India is a better country to live in than their own countries.

In some respects, I am very proud. But while being proud, I would like to say, at the same time, that we cannot remain complacent because India would have to be kept safe for future generations. We have also to take into account the population increase and the area of the country. Therefore, we have to preserve our land. We have to protect our country from the foreigners for the sake of our future generations.

When I was a Minister in Mizoram, in 1984, I was sent to repatriate the Chakma refugees who had come from Bangladesh. When I saw them, I sympathised with them very much. As a human being, I have love and affection for my fellow human beings. They were asking me, they were requesting me, to allow them to remain in India. They said that they would rather die here than be sent back to their country. In spite of the sympathy I had for them, I told them: 'Brothers and Sisters, it is far better to die in your native land than to die in India: you please go back to your native land and die there peacefully'.

[Shri Hiphei]

I told them: 'India is not your native land; you are not supposed to die here, in India'. After a week, they were repatriated; they were sent back. In the same manner, all the foreigners who have come to our country, illegally, should be repatriated, should be sent back.

Madam, today, in Arunachal Pradesh, we have some 80,000 refugees— if the number is not correct, I may kindly be corrected — who are still there. They have not been given Indian citizenship. They have been allowed to remain there for such a long time. Even the Supreme Court had given a judgment that they were foreigners. So we have such cases in North-East India. The Government of India have to be very, very cautious and careful about the refugees. We must take a firm stand to see that this land is protected for the future children of India. Otherwise, as I said earlier, the land will never increase. Only the population will increase. So, what about our future generations? We have to think of them today very, very seriously.

When I speak about foreigners, I would like to go a little further. Today some of the States in North-East India are called restricted areas. If any foreigners has to go there, he has to get a Restricted Area Permit. But those foreigners who want to visit the North-Eastern States are not foreigners from our neighbouring countries. They are from advanced countries. Most of them are from the western countries, who do not want to stay in India permanently. So, why should we restrict their entry? What is the meaninig of the Restricted Area Permit? If we want our tourism to grow, this Restricted Area Permit system should be abolished or, at least, relaxed. Otherwise, tourism cannot be improved there. So I would like to appeal to the Home Ministry that this Restricted Area Permit system may kindly be abolished once for all so that the North-Eastern States also are visited by foreign tourists. Let those States have their own resource or income, let them have their own revenue. Most of the North-Eastern States are called 'special category States" and they are solely dependent upon the financial assistance of the Union Government. So I would like to appeal to the Home Ministry, earnestly and humbly, that this Restricted Area Permit system should be abolished or relaxed.

To go to some places, they say an Inner Line Permit is required. Some time back, I met a journalist. He was saying, "Mizoram is my home. Why should I not be allowed to enter my home?" I said, "No. My friend, India is our home Mizoram is one of the rooms. India is a very big house. But if we are going to enter one of the rooms; where a newly-married couple is staying, without knocking, it is not good".

The Peace Accord was signed in 1986 only. This Inner Line Permit system is based on the Chin Hills (Regulation) Act. This has nothing to do with the Restricted Area Permit. This is only to protect the special interests of the minorities of the North-Eastern States. So, these two important things need not be linked together. The Restricted Area Permit has its own meaning, and the Inner Line Permit has its own meaning.

When India became independent, it was first divided into sixteen rooms. The framers of our Constitution had in their mind that in one of the rooms there should be children who could not go along with the dominant group. So, they provided the Sixth Schedule to the Connstitution of India. The Sixth Schedule is like a screen in one of the corners of the room. Those areas where we need the Inner Line Permit are one of the corners. They were all in the Assam State. Those days Assam was very big. In the corner of that

room, there are many sections of people who are thought to be children who can be easily assimilated by the dominent group. That is why there was a screen, a *purdah* just to protect their special interests. That is the Sixth Schedule provision.

On that basis, the Autonomous District Councils came into being. Today, throughout India we have only nine Autonomous District Councils. Altogether we have only nine Autonomous District Councils where we have now children who can be easily assimilated. That is why the Inner-Line Permit is required.

Why should we need the Inner-Line Permit and the Restricted Area Permit together? So, I would like to appeal to the Home Minister that the Inner-Line Permit be allowed to remain as it is today so that they also can grow up according to their special interests. That is the reason why we have the Sixth Schedule Provision in the Constitution. This may kindly be remembered. And the Restricted Area Perrmit may be lifted.

Madam, I am very happy that this Bill has been brought in by my senior colleague. It is a very very important Bill. As I have said, we have to protect the land for all our children. So, let us take it very seriously so that we can avoid the influx of foreign nationals from nationals from our neighbouring countries.

Thank you very much, Madam.

*SARADA MOHANTY (Orissa): Madam, Vice-Chairman, I rise to support The Prevention of Influx of Fireign Nationals in the Country Bill, 1991 moved by my friend Shri Krishan Lal Sharma in this august House. The influx of foreign nationals to our country is a far greater problem for us than price-rise and unemployment. The foreign nationals who have been staying in our country illegally are posing a severe threat to the unity, integrity and security of our country. They are creating irrepairable damage to our national character. They are also an unnecessary burden on our country's economy.

Madam, I am reminded of the political atmosphere which prevailed during Sepoy Mutiny. We fought against the Britishers as a nation. Our Leaders showed examplary courage and unity against the enemy. Now the time has come to remember that heroic period of history. But unfortunately that unity among us is missing. There cannot be a sadder thing than this.

Madam, the illegal influx and settlement of foreign nationals in our country is slowly becoming a very complex problem. The most shocking aspect of this problem is that nobody knows the number of the foreign nationals who are staying illegally in different parts of the country. My information is that the number of these people exceeds the list maintained by the government. for example. Madam, Vice-Chairman if you go to Paharganj area of Delhi you would come across a number of these people moving on the streets without any fear of the law of the land. They are staying in hotels, rented houses like any other genuine citizen of India. They are also carrying passport and other travel documents, but unfortunately the Police Constable would never be able to prove whether those documents, are genuine or fake. In actuality they are carrying all forged documents like passport etc. By paying extra penny they are able to silence the landlord in whose house they are staving on rent. The landlords also do not reveal the identity of these

*English translation of the original speech delivered in Oriya.

[Sarada Mohanty]

foreign nationals who are staying illegally in their houses. You would never be able to know about their activities. Very often they are indulged in activties which are against the interest of our country. In today's newspaper there is a news about a bomb being planted in a Cinema Hall at Cannaught Place. It has also come in the news that a foreign national is responsible for this activity. I can speak with responsibility that these acts of sabotage are being committed by foreign nationals who are staying illegally and without any genuine documents and reason in India. The citizens of our country are unable to live in peace. They are living under a persistent fear of kidnappings, arson, riot, bomb-blasts and social tension. In urban areas the situation is so bad that people are sceptical of reaching their homes safely from their workplaces.

Madam, there is another dimension to this problem. The foreign nationals who are staying illegally in the country are engaged in the most-profitable business called drug trafficking. Their purpose is to make quick money at the cost of the youths of our country. There is no beetle-shop in big cities where drugs are not available. The young boys are getting addicted to drugs and thereby harming themselves and their families. So these people are responsible for damaging our national character. The parents of the drug-addicted young boys suffer mental agony. Drug addiction leads these young boys to committ other social and economic crimes. Ultimately it is harmful for the country.

Madam, Vice-Chairman, we come accross news about bank-forgery and such other economic crimes. These people are at it. These people are also a burden on the economy of our country. For no valid reason at all we are feeding them from our stock of foodgrains. Had they not been staying here we would have been able to export that surplus foodgrains and earn foreign-exchange, for our own country.

Madam, I am reminded of my childhood days when there was a deep sense of fellow-feeling and good will among members of different communities during festivals like Dussehra and Muharram. But now that cultural and social involvement and merry-making are very much lacking among people of different communities. Now the seeds of suspicion have been sown among them. This is highly dangerous for the unity and integrity of a secular county like India.

Madam, Vice-Chairman, before concluding I would like to speak a few words on the adverse effect of these foreign nationals on the election process in our country. These people in some parts of the country like Assam are trying to enlist their names in the voters' list and thereby claim citizenship of India. This is highly detrimental to the interest of our people. It is essential for our government to identify the foreign nationals who are illegally staying in our country. The voters' list should be revised and their names should be deleted from it. The Officers who are responsible for this type of malpractice should be pulled up. They are taking the matter very casually. There are such people who have been staying illegally for ten to twelve years in India. Such people should be identified and sent back to their countries. Government should fence the border strongly in order to check such infiltration.

I urge upon the honourable Minister to accept this bill moved by my friend Mr. K. L. Sharma.

Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Dr. B. B. Dutta-abcent. Shri Murli Manohar Joshi.

डा० **मुरली मनोहर जोशी** (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं श्री कृष्ण लाल शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर यह विधेयक सदन के सामने विचारार्थ रखा है। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश बेहोशी में है और जब कभी ऐसे विधेयक आते हैं तब मैं यह मानता हूं कि देश को बेहोशी में (व्यवधान)

ANNOUNCEMENT REGARDING WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM EGYPT

THE VICE-CHAIRMAN (KUMARI SAROJ KHAPARDE): Hon. Members, I have an anouncement to make. We have with us, seated in the Special Box, Members of the Parliamentary Delegation from Egypt, currently on a visit to our country, under the distinguished leadership of His Excellency, Dr. Ahmed Fathi Sorour, Speaker of the People's Assembly of Egypt. I, on my own behalf and on behalf of the Members of the House take pleasure in extending a hearty welcome to the leader and other Members of the Delegation and wish that our distinguished guests will have an enjoyable and fruitful stay in the country. We hope that during their stay here, they would be able to see and learn more about our Parliamentary system, our country and our people and their visit to this country will further strengthen the friendly bond that exists between India and Egypt. Through them, we convey our greetings and best wishes to the Members of the People's Assembly and the friendly people of Egypt. Thank you.

THE PREVENTION OF INFLUX OF FOREIGN NATIONALS IN THE COUNTRY BILL, 1991--contd.

डा० **मुरली मनोहर जोशी** : मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और श्री कृष्ण लाल शर्मा जी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत उचित समय पर इस विधेयक के द्वारा सरकार का और देश का ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा की है और देश को बेहोशी से जगाने की चेष्टा की है। पिछले दिनों इस देश में जिस तरह से घुसपैठ बढ़ी है, इनफिल्ट्रेशन बढ़ा है उससे सारे देश को चिंता हो रही है। बंगला देश से जो घुसपैठ हुई है उसका अनुमान बहुत आसानी से लगाया जा सकता है कि वह कितनी ज्यादा संख्या में हुई है। देशों की जनगणना की तुलना से, बंगला देश और भारत की 1991 की जनगणना की तुलना से इसका अंदाज लग सकता है। बंगला देश की 1991 में अनुमानित जनसंख्या 10 करोड़ 48 लाख और वार्षिक वृद्धि दर 2.02 प्रतिशत थी, जबकि 1981 में यह दर 3.13 प्रतिशत रही थी। बंगला देश की सरकार ने पहले 1991 की जनसंख्या का अनुमान लगभग 11 करोड़ 40 लाख लगाया था, यू०एन०डी०पी० का अनुमान 11 करोड़ 60 लाख 1990 में था और 11 करोड़ 60 लाख 1991 में था। और 11 करोड़ 80 लाख 1991 में था। इस प्रकार बंगला देश की सरकार के अनुमान से लगभग 90 लाख जनसंख्या 1991 में कम रही, जबकि यू०एन० डी०पी० के अनुमान से लगभग एक करोड़ कम रही। सवाल उठता है कि यह एक करोड़ लोग कहां चले गए? बंगाल की खाड़ी में, बर्मा में, अराकान में या हिन्दुस्तान में। मैं सिद्ध करना चाहूंगा कि यह एक करोड़ लोग बंगला देश से हिन्दुस्तान आए। जनगणना के अन्य आंकड़ों से यह भी प्रतीत होगा कि 70 लाख कम से कम और एक करोड़ 20 लाख के लगभग इन 10 वर्षों में 1981 से 1991 तक बंगला देश के लोग यहां आए। त्रिपुरा से हमारे मित्र यहां बैठे हुए हैं। उनको मालूम